राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी

सादर प्रकाशनार्थ :-

सरकार किसानों का दमन करना बंद करें : पायलट

जयपुर, 25 अप्रेल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार से मांग की है कि ऐटा-सिंगरासर माईनर मांग को लेकर गत् दो दिनों से सूरतगढ़ थर्मल से दो किलोमीटर दूर ग्राम ठुकराना में महापड़ाव डालकर बैठे किसानों से वार्ता कर उनकी वाजिब मांग का समाधान करें।

श्री पायलट ने आज बयान जारी कर कहा कि सरकार किसानों की वाजिब मांग को गंभीरता से नहीं ले रही। गत् मार्च माह में भी किसानों द्वारा उक्त मांग के लिए जब महापड़ाव शुरू किया था तब सरकार ने समाधान निकालने के स्थान पर किसानों के खिलाफ बर्बरपूर्ण कार्यवाही करते हुए लाठियां व गोलियां बरसायी थी, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिखावे के लिए तो दावा करती है कि किसान और खेती उसकी प्राथमिकता है, परन्तु दूसरी ओर सूखे का सामना कर रहे किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। केन्द्र व राज्य के बजट में सिंचाई के पेटे बड़ी राशि की थोथी घोषणा की गई है इसलिए धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जिन योजनाओं की डीपीआर बन चुकी है उन पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐटा-सिंगरासर नहर की डीपीआर बन चुकी है और यदि सरकार इस परियोजना को मंजूरी दे देती है तो सूरतगढ़, पीलीबंगा, नोहर और लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्रों के 53 गाँवों की 6 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी ंषि सिंचाई योजना की घोषणा की है और प्रदेश सरकार ने भी बजट में दावा किया था कि बड़ी राशि सिंचाई के लिए पहले भी आवंटित हो चुकी है और आगे भी की जाएगी। परन्तु राजस्थान को क्या मिला यह बड़ा प्रश्न है।

उन्होंने कहा कि ंषि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है इसलिए आवश्यक है कि सरकार थोथी घोषणाएं करने के स्थान पर सिंचाई के लिए जितनी डीपीआर बन चुकी है उन्हें शीघ्र मंजूरी दे ताकि किसानों की फसलों को चौपट होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की माँगों के प्रति गम्भीर रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि सरकारी अनदेखी के शिकार किसान बदहाली का सामना कर रहे है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी

सादर प्रकाशनार्थ :-

जयपुर, 25 अप्रेल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट ने आज नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सर्राफा व्यापारियों द्वारा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ दिये गये धरने को सम्बोधित किया।

श्री पायलट ने अपने सम्बोधन में कहा कि केन्द्र सरकार ने आभूषणों पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाकर अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है। क्योंकि सरकार के इस निर्णय से सर्राफा व्यापार प्रभावित होने के साथ ही अनगिनत संख्या में आभूषण व्यवसाय के कामगार बेकार हो गये है। सरकार के इस निर्णय ने इंस्पेक्टर राज को बढ़ाकर सर्राफा व्यापारियों के प्रताडना का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि गत् यूपीए सरकार के समय जब इसी प्रकार के विषय पर विचार किया गया था तब केन्द्रीय मंत्री रहते हुए मैंने तथा अन्य तत्कालीन केन्द्रिय मंत्रियों एवं कांग्रेस नेताओं ने वित्त मंत्री से मिलकर इसे लागू नहीं करने का निवेदन किया था और तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस वाजिब मांग को सर्राफा व्यापारियों के हित में बिना विलम्ब मान लिया था।

उन्होंने कहा कि सर्राफा व्यापारी भाजपा सरकार की वादाखिलाफी के कारण दूसरी बार हड़ताल करने पर मजबूर हुए है जो बताता है कि सरकार उनकी औचित्यपूर्ण मांग के समाधान के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकशाही में जनता की मांग पर सरकारी अहम् हावी नहीं होना चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार ई.पी.एफ. पर लिये अपने अविवेकपूर्ण निर्णय को वासप लिया है, उसी प्रकार व्यापक जनहित में सर्राफा व्यापार पर लगे उत्पाद शुल्क को बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये अविलम्ब वापस लेना चाहिए।